International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-8, Issue-3 May-June- 2021
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

नई शिक्षा नीति 2020 के बहुआयामी प्रभाव

राधारानी
शोध छात्रा
विभाग शिक्षा
महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर

डॉ वसुंधरा
पर्यवेक्षक

सार

शिक्षा राष्ट्र की आधारशिला है क्योंकि यह देश और इसके नागरिकों की वृद्धि और विकास में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। कोई भी इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता है कि शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पूर्व अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष डॉ कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले एक पैनल की सिफारिशों के आधार पर, नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है जो समानता पर केंद्रित है, हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। इस पत्र में, लेखक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन में मुद्दों और चुनौतियों के बारे में पता लगाने जा रहे हैं, जो प्रमुख क्षेत्र गायब हैं, और इसमें शामिल जटिलताएं हैं। अंतिम लेकिन कम नहीं, पेपर हाल के डेटा आंकड़ों के साथ–साथ नीति और प्रथाओं के बीच विभाजन पर भी चर्चा करता है। नई शिक्षा नीति में बदलाव के कारण संभावित चुनौतियों से संबंधित सभी विवरणों का विश्लेषण इस पत्र के आगामी खंडों में किया गया है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य विदेशों में सभी लोगों को उच्च गुणवत्ता, विभिन्न विविधता और गतिशील शिक्षा केंद्र प्रदान करके हमारे देश को शिक्षा के लिए एक वैश्विक विकल्प बनाना है। यह नीति शिक्षा क्षेत्र में व्यय को जल्द से जल्द सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाने पर केंद्रित है। शिक्षा नीति कोई नई संरचित नीति नहीं है, बल्कि यह विभिन्न चरणों का संकलन है।

शिक्षा मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक रूपों के माध्यम से होता है। गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। भारत की सतत प्रगति, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक प्रगति, समानता, राष्ट्रीय एकता, संस्कृति के संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच आवश्यक है। यह शिक्षा का वह माध्यम है जिससे देश की प्रतिभा और संसाधनों का विकास कर विश्व शांति की कामना की जा सकती है।

मुख्य शब्द

नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, कोविड–19

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 100% नामांकन के साथ सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। विभिन्न सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि बच्चों को सीखने की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय के करोड़ों छात्रों में बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान तक की कमी है। आगे की शिक्षा के लिए संख्याओं को पढ़ने और लिखने और कुछ बुनियादी संचालन करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान एक राष्ट्रीय अभियान बन जाएगा। 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता एवं अंकज्ञान शिक्षा व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने से छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में यह अनुपात 25 से कम होगा। बच्चों में रटने की क्षमता को दूर कर लर्निंग टू लर्निंग पर जोर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से स्कूली स्तर पर मूल्यांकन के तरीकों में आमूल–चूल परिवर्तन किया गया है। हमारी शिक्षा प्रणाली योगात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित है जो मुख्य रूप से याद करने और याद रखने के कौशल पर केंद्रित है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर ले जाना है जो अधिक उपयोगी है और हमारे छात्रों में सीखने और विकास को बढ़ावा देता है। रचनात्मक मूल्यांकन स्पष्ट रूप से छात्रों की उच्च स्तर की दक्षताओं जैसे विश्लेषण, तार्किक सोच, वैचारिक सोच को दर्शाता है। विद्यार्थियों के प्रगति पत्र के प्रारूप को नया रूप दिया जाएगा।

शिक्षा के मुख्य रूप से तीन बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा व्यवस्था इन्हीं तीनों के इर्द–गिर्द घूमती है। छात्र किसी भी शिक्षा का केंद्र होता है। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नींव के चरण से ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा छात्रों को सकारात्मक सीखने का वातावरण प्रदान किया जाएगा। इससे उनकी शिक्षा की नींव मजबूत होगी। छात्रों को उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा सीखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए पूर्व छात्रों और समुदाय के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्रों को माध्यमिक स्तर पर विषयों के चुनाव के लिए विकल्प दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हर साल माध्यमिक शिक्षा की विशेषता होगी समग्र विकास और विषयों का चुनाव। कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्यवसाय आदि पाठ्यक्रमों की श्रेणियां समाप्त कर दी जाएंगी। भविष्य में छात्रों को बेरोजगारी का दंश न झेलना पड़े। इसके लिए कक्षा 6 से ही उन्हें कई तरह के हुनर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्रों को भारतीय भाषाओं के अलावा कई विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार की भाषाओं को जानने से छात्र भारतीय संस्कृति के साथ–साथ विश्व संस्कृति को जानकर अपने वैश्विक ज्ञान में वृद्धि करेंगे।

शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा बढ़ते समाज में बढ़ते हुए मनुष्य से संबंधित है। शिक्षा प्रणाली को छात्रों को शिक्षार्थी, नवप्रवर्तक, विद्वान, शोधकर्ता और प्रशिक्षक बनाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दशकों के दौरान एक मजबूत और निरंतर आर्थिक विकास के बावजूद, भारत अभी भी सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और शिक्षा में सुधार ही चुनौतियों का समाधान करने और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका है।

नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में मौजूद विभिन्न कमियों को दूर करना है और इस नीति के माध्यम से भारत को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करके 2030 के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। हालाँकि, नीति को नए प्रस्तावित निकायों की स्थापना, स्कूलों के लिए नियमों और विनियमों को परिभाषित करने और नई शिक्षा नीति 2020 के साथ विभिन्न योजनाओं और अधिनियमों के अभिसरण स्थापित करने के लिए राज्य और केंद्रीय अधिकारियों के बीच तत्काल सहयोग की आवश्यकता है। जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों के बीच कौशल विकसित करने के लिए, मास्टर संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। जैसा कि नीति का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद का 6% निवेश करना है, यह सुझाव दिया जाता है कि ब्लॉक चेन, एआई और भविष्य कहनेवाला विश्लेषिकी उद्योग में उद्योग भागीदारों के साथ अनुसंधान में उद्योग की भागीदारी के साथ एक सतत सहयोग होना चाहिए, अल्पावधि प्रदान करना कौशल प्रमाणपत्र और ऑनलाइन विश्वविद्यालयों के निर्माण में सह–भागीदारी। गुणवत्ता में वृद्धि के लिए अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता में वृद्धि के माध्यम से एचईआई में विस्तार का अवसर है। इसके अलावा, एचईआई के साथ अनुरूपित व्यावसायिक कार्यक्रम विकसित करने की गुंजाइश है जो रोजगारोन्मुख और सस्ती कीमतों पर हो सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को विभिन्न भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री आदि को विकसित करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। हालाँकि, सिस्टम में अराजकता पैदा करने के बजाय भाषाओं की सूची को परिभाषित करना अनिवार्य है क्योंकि इसके लिए पूर्ण बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होगी, प्रत्येक स्कूल में भाषा शिक्षक की भर्ती और मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करना होगा। जबकि, नई शिक्षा नीति 2020 अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाने के लिए शैक्षिक प्रणाली को नया रूप देने के अवसर प्रदान करती है, नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्यों के समर्थन के अलावा इसके लिए बहुत सारे बुनियादी ढांचे और संस्थागत पुनर्गठन की आवश्यकता है।

नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव

हमारे समाज में शिक्षा जो भूमिका निभाती है, उसमें एक कुशल और ज्ञानवान कार्यबल का निर्माण शामिल है, प्रतिभा की खेती को सक्षम बनाता है, तर्कसंगत नागरिकों का पोषण करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और उत्पादकता बढ़ाता है। यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए भी काम करता है, समाज के सदस्यों के बीच स्वीकृति, सम्मान और समानता को

विकसित करता है। शिक्षा की शक्ति इस मायने में अद्वितीय है कि यह आत्म–संवर्धन की अनुमति देती है, क्षितिज को व्यापक बनाती है और नए दृष्टिकोणों तक पहुंच प्रदान करती है। शिक्षा का पूरा उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार वैश्विक नागरिकों का निर्माण करना है।

एक राष्ट्र के विकास, गरीबी उन्मूलन और सामान्य रूप से हमारे सभी जीवन में शिक्षा की भारी भूमिका के कारण, एक मजबूत शिक्षा नीति की आवश्यकता सामने आती है। एक मजबूत शिक्षा नीति और प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमीकरण, साधन–साध्य संबंध, शैक्षिक विचारों की निरंतरता और परिवर्तन को समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए, एक शैक्षिक ढांचा जिसकी सभी राष्ट्रों को आवश्यकता है, प्रासंगिक, यथार्थवादी, अनुकूलनीय, समावेशी, लागू करने योग्य और समर्थित होना चाहिए। शिक्षा द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, यह सर्वोपरि हो जाता है कि नीतियां हमेशा विकसित होती हैं और प्रणाली कमियों से मुक्त होती है।

नई शिक्षा नीति, 2020 के उज्ज्वल पक्ष को देखते हुए, तीन से पांच वर्ष की आयु के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा को शामिल करने की विभिन्न शिक्षाविदों और स्कूली शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा सराहना की गई है। नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चों को जल्दी शुरुआत करने में मदद मिलेगी क्योंकि यह आजीवन सीखने की नींव तैयार करेगा।

नीति की पहचान है कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत से अधिक विकसित हो जाता है और सीखने के शुरुआती चरणों में स्वस्थ मस्तिष्क के विकास और विकास के महत्व पर बल देता है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण से बच्चे के मस्तिष्क की उचित देखभाल और उत्तेजना के लिए गतिविधियों को पाइपलाइन में लाने में मदद मिलेगी। इस तरह की प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा युवा दिमाग के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसे ढालने के चरण में उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बच्चों की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करके, प्रारंभिक बचपन और शिक्षा पर ध्यान देने से हमारे कल के नेता बेहतर तैयार होंगे।

विषय विकल्पों में लचीलापन न केवल छात्रों को उन विषयों को चुनने की अनुमति देगा जो वे पसंद करते हैं या विशेष रूप से मजबूत हैं बल्कि उन्हें अपने निपटान में विभिन्न प्रकार के करियर पथ रखने में भी मदद मिलती है। व्यक्तिगत रुचि और पसंद के विषयों का अध्ययन, छात्रों को गहराई से अध्ययन करने और उनके ज्ञान के साथ–साथ उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। यह सामान्य रूप से शिक्षा प्रणाली के लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि यह इसे दुनिया भर के विकसित देशों में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों के समकक्ष लाएगा।

भारत में वर्ग–आधारित असमानता बढ़ेगी क्योंकि जो लोग अंग्रेजी शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम हैं, वे भीतरी इलाकों की प्रतिभा से आगे निकल जाएंगे। भारत के आर्थिक विकास में अंग्रेजी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इसे पर्याप्त श्रेय देना महत्वपूर्ण है। अत यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल शिक्षा का ही अधिकार नहीं है, अपितु अंग्रेजी माध्यम की

शिक्षा का भी अधिकार है। यह नीति न केवल एक समान शिक्षा के दृष्टिकोण को पराजित करती है जो एक विकसित, समृद्ध और न्यायसंगत समाज के लिए सर्वोपरि है बल्कि कुछ हद तक लैंगिक असमानता को भी जन्म देती है। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण, माता–पिता अपने बेटों को अपनी लड़कियों के बजाय एक निजी स्कूल में पसंद करते हैं। यह समाज में दो लिंगों के बीच की खाई को बढ़ाएगा, एक ऐसा समाज जिसमें पुरुष महिलाओं को अपने अधीन मानते हैं। यह एक मुद्दा बन जाता है जब नई शिक्षा नीति और पब्लिक स्कूल अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं होते हैं और विशेष रूप से हाशिए पर हैं।

सामाजिक न्याय से वंचित उच्च शिक्षा के निजीकरण की सम्भावना को लेकर कई शिक्षाविदों, शिक्षा विशेषज्ञों और संगठनों ने नई शिक्षा नीति की भर्त्सना की है। भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय सरकार से संबद्धता की एक प्रणाली का पालन करते हैं जो उन्हें अपने संचालन में पूर्ण स्वायत्तता नहीं देती है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य पंद्रह वर्षों में किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्धता की व्यवस्था को समाप्त करना है। इससे संस्थानों को न केवल शुल्क संरचना, कार्यप्रणाली आदि के बारे में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि निजीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। शिक्षा प्रणाली को बदलने का यह प्रस्ताव भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों तक छात्रों की पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

इसके परिणाम विशेष रूप से गांवों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में प्रचलित होंगे जो उच्च शिक्षण शुल्क के कारण कॉलेज का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उन कॉलेजों के समान हो जाएगा जो ज्यादातर निजीकृत हैं और अत्यधिक उच्च शुल्क वसूलते हैं। यह अधिकांश अमेरिकी छात्रों को छात्र ऋण लेने और यहां तक कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कॉलेज जाने के अपने सपने को छोड़ने का कारण बनता है। निम्न–आय वाले परिवारों से संबंधित भारतीयों के लिए एक स्पष्ट समानांतर रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार, लंबी अवधि में, नई शिक्षा नीति गरीबों के उत्थान के बजाय अमीरों और अमीरों के बीच की खाई को और बढ़ाने में मदद करेगी, जो बदले में देश के विकास और वृद्धि में बाधा के रूप में कार्य करेगी।

एक और पहलू जिसने देश भर में कई लोगों का ध्यान खींचा वह यह है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में बिल्कुल चुप है। जबकि अधिनियम बड़े पैमाने पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में बात करता है, यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाने में विफल रहता है। इसलिए, इसे वास्तविकता बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कोई अनिवार्य तंत्र नहीं है।

विश्वविद्यालयों को मौजूदा और भविष्य के संकट से जुड़े विभिन्न खतरों का सामना करने के लिए लचीलापन, लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के प्रति झुकाव, अंतर–व्यक्तिगत भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सकारात्मक मानसिकता, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच रखने वाले छात्रों को मंथन करने की आवश्यकता है। जुड़ाव के नए मॉडल जैसे कि सरकार, संस्थानों, प्रकाशकों, पूर्व छात्रों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, कॉर्पोरेट पेशेवरों, दूरसंचार ऑपरेटरों जैसे विविध हितधारकों वाले लर्निंग कंसोर्टियम और गठबंधन को

स्केलेबल, टिकाऊ और समावेशी मिश्रित शिक्षा के लिए स्थापित करने की आवश्यकता है। डिजिटल दक्षताओं को विकसित करने में छात्रों और संकायों को प्रशिक्षित करने का यह सही समय है ताकि वे डिजिटल रूप से धाराप्रवाह बन सकें और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से नियोजित कर सकें। दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ (मिश्रित शिक्षा) का उपयोग करने के लिए, संस्थानों को गुणवत्ता सामग्री का उत्पादन या खरीद करने, संसाधनों को प्रभावी ढंग से नियोजित करने और व्यवस्थित रूप से ठोस कार्यों की योजना बनाने पर सख्ती से काम करने की आवश्यकता है ताकि यह संस्थागत दृष्टि और नीतियों के साथ अच्छी तरह से संरेखित हो।

सबसे आम आलोचना यह है कि यह उन लोगों के बीच की खाई को चौड़ा करेगा जो अंग्रेजी में संवाद कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। एक और चुनौती यह है कि उन भाषाओं के लिए नई शिक्षण सामग्री विकसित करना जिनका मानकीकरण नहीं किया गया है या जिनके पास लिपि नहीं है, एक कठिन कार्य होगा जिसके लिए भारी प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होगी। यह एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि इस अतिरिक्त लागत को कौन वहन करेगा, क्या यह सरकार या स्कूल होंगे या माता–पिता पर अप्रत्यक्ष बोझ डाला जाएगा, या इसे सभी द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

एक अन्य बिंदु जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि स्कूल में शिक्षा के माध्यम के रूप में कौन सी मातृभाषाध्स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए और किसे नहीं। उदाहरण के लिए, राभा, संथाली और नेपाली जैसी स्थानीय भाषाएं बोलने वाले छात्र कोकराझार और चिरांग क्षेत्रों में असमिया–माध्यम के स्कूलों में जाते हैं, तो जिन बच्चों को अपनी घरेलू भाषा में पढ़ाने से लाभ होना चाहिए था, वे हार जाएंगे, परस्मिता सिंह ने कहा, जो असम के कोकराझार और चिरांग में आदिवासी और गैर–आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में सहायता प्रदान करने वाले प्रथम स्कूल कार्यक्रम के साथ काम करता है और यही स्थिति उन बच्चों के साथ होगी जिनके माता–पिता के पास स्थानांतरणीय नौकरियां हैं। मैं फिर से एक उदाहरण उद्धृत करना चाहूंगा, मान लीजिए कि बच्चा उत्तर भारत के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, जहां शिक्षा का माध्यम हिंदी है और उसके पिता केरल में स्थानांतरित हो गए, अब वहां स्कूलों में शिक्षा का माध्यम कन्नड़ है, तो यह बच्चे के लिए कुछ भी पकड़ना या समझना बहुत मुश्किल हो जाता है।

यदि नीति को प्रस्तावित तरीके से लागू किया जाता है तो यह उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भी एक चुनौती होगी, जहां शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं है, लेकिन आम तौर पर अंग्रेजी या हिंदी जैसी सामान्य भाषा है, छात्रों के बीच भाषा अवरोध पैदा होगा और ऐसा हो सकता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने में कठिनाई हो। आखिरकार, यह छात्रों के साथ–साथ शिक्षकों के लिए भी एक रस्साकशी बन जाती है। संक्षेप में कुशल भाषा शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त शिक्षण सामग्री और उचित रोड मैप की कमी जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। किसी विशेष स्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए भाषा को एक वाहन के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी संचार और सशक्तिकरण की एक वैश्विक भाषा है और सरकार को दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए बीच का रास्ता तलाशने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना कि लोग जड़ों से जुड़े रहें और साथ ही बाहरी दुनिया के साथ आत्मविश्वास से संवाद करने में सक्षम हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 6वीं कक्षा से शुरू होने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अनिवार्य किया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को स्थानीय शिल्प, बढ़ईगीरी, खाना पकाने, बागवानी आदि जैसे कौशल सिखाए जाएंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में प्रमुख चुनौतियों में से एक उचित संसाधनों की कमी है। स्कूल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, मुख्य रूप से 3चीजों की आवश्यकता होगी – बुनियादी ढांचा, स्थापित और प्रशिक्षित कर्मियों और एक ही सवाल उठता है कि इन अतिरिक्त लागतों को कौन वहन करेगा क्योंकि इसके लिए उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। इसका एक समाधान यह हो सकता है कि स्कूल स्थानीय शिल्पकारों के साथ साझेदारी कर सकते हैं जिनके पास उचित बुनियादी ढाँचा और सेटअप है। हालांकि यह विकल्प पैसे बचाने के मामले में बेहतर है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान भी हैं। यहाँ फिर से चुनौती यह है कि जब आप छात्रों को इस प्रकार के स्थानों पर ले जाते हैं तो जोखिम कारक होते हैं। यह परिवहन के संबंध में स्कूल के लिए एक उपरि है और यह माता–पिता के लिए फीस का भुगतान करने के लिए एक उपरि है। साथ ही, यदि स्थान बहुत दूर है तो यात्रा करने में बहुत समय बर्बाद होता है क्योंकि स्कूल को सीमित समय के भीतर बहुत सारे पाठ्यक्रम को कवर करना होता है।

निष्कर्ष

किसी भी नीति के क्रियान्वयन का अपना महत्व होता है। एक कुशल कार्यान्वयन किसी नीति को बड़ी सफलता बना सकता है और दूसरी ओर, यदि कार्यान्वयन अच्छा नहीं है, तो यह एक बड़ी आपदा हो सकती है। स्कूल स्तर पर विभिन्न प्रकार की धाराओं को समाप्त कर दिया गया है, जिससे छात्रों में मनोवैज्ञानिक दबाव कम होगा। नीति 2020 में विद्यार्थी को शिक्षा का केंद्र मानकर पाठ्यक्रम तैयार करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से आगे के छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देकर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास दिखाई दे रहा है।

संदर्भ

1. बी.एल. गुप्ता और ए.के. चौबे। 2021. उच्च शिक्षा संस्थान – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में स्वायत्तता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए कुछ दिशानिर्देश। सभी अनुसंधान शिक्षा और वैज्ञानिक विधियों का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम। 9, अंक 1, जनवरी, 2021, आईएसएसएन 2455–6211, इम्पैक्ट फैक्टर 7.429। पीपी। 72–84
2. चोपड़ा, रितिका (2 अगस्त 2020) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना। द इंडियन एक्सप्रेस।
3. डॉ. डी पी शर्मा भारतीय शिक्षा प्रणाली में चुनौतियाँ पर। एडुवॉयसद्य शिक्षा उद्योग की आवाज। 25 मई 2020
4. आइंस्टीन ए। हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के साथ हल नहीं कर सकते हैं जो हमने उन्हें बनाते समय इस्तेमाल किया थाय 2020.

5. जेबराज, प्रिसिला (2 अगस्त 2020) हिंदू बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित है? हिन्दू। आईएसएसएन 0971–751

6. नंदिनी, एड। (29 जुलाई 2020) नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं। स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हिन्दुस्तान टाइम्स

7. चार्ल्स डार्विन द्वारा पापाथानसियौ एम उद्धरण, सर्वश्रेष्ठ कोटेशन 2020.

8. शुक्ला, अमनदीप (29 जुलाई 2020) नई शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक तय किए हिंदुस्तान टाइम्स